G नगर •
वर्ष 17 | अंक 293 | पृष्ठ : 16+8+16
मूल्य : साढ़े चार रुपये
6 राज्य • 2 केंद्रशासित प्रदेश • 21 संस्करण

अमर उजाला

नई दिल्ली
शुक्रवार, 31 जनवरी 2020

कोरोना का कहर केरल में मिला पहला मरीज, चीन में मरने वालों की संख्या 170 पार — दिल्ली-एनसीआर

रियल एस्टेट को मिली गति तो खरीदारों को होगा फायदा

बजट उम्मीद 2020-21 ₹

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा/ ग्रेटर नोएडा। बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। बिल्डरों और डेवलपर्स की ओर से रियल एस्टेट को उद्योगों का दर्जा दिलाने, फाइनेंस के संकट को दूर करने, धन के आवंटन, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित कई घोषणाओं की दरकार है। उनकी मानें तो इस बजट में उन्हें काफी कुछ मिल सकता है। बिल्डरों का उनका कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिली तो इसका सीधा फायदा खरीदारों को भी होगा। साथ ही सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।

उम्मीद है कि बजट 2020 में रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की घोषणा की जाएगी। सरकार को घर खरीदारों के लिए कर में लाभ बढ़ाना चाहिए। - **विजय वर्मा, सीईओ, सन वर्ल्ड ग्रुप**

जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को फिर से शुरू करने की घोषणा के लिए भी हम आशावान हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ के साथ, इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में सीधे तौर पर गिरावट होगी। - **अमित मोदी, डायरेक्टर, एबीए कॉर्प और प्रेसीडेंट इलेक्ट, क्रेडाई वेस्टर्न यूपी**

रेरा, स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसे कंसोलिडेशन के सुचारु कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति और बैंकों द्वारा युक्तिसंगत फंडिंग की कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। - **रतन हवेलिया, संस्थापक व चेयरमैन, हवेलिया ग्रुप**

जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फिर से शुरू किए जाना चाहिए। जीएसटी के दायरे में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लाना अगर बजट में शामिल होता है तो सराहना की जाएगी। - **मनोज गौड़, एमडी, गौड़ ग्रुप और प्रेसीडेंट, किफायती आवास समिति, क्रेडाई**

अप्रुवल की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अधिक निवेश और सिंगल विंडो क्लीयरेंस को पारित करना चाहिए। उम्मीद है सरकार कुछ घोषणाओं के साथ आएगी। - **वैभव जैन, सीएमडी, राइज ग्रुप**

रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्टांप ड्यूटी में कटौती करें। वहीं 25000 करोड़ के फंड एआईएफ के साथ-साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोत्साहन प्लान भी लाए जाएं। - **अशोक गुप्ता, सीएमडी, अजनारा इंडिया लिमिटेड**

पिछले वर्ष प्रोपर्टी में निवेश से टैक्स हटाया गया था। इस बार सरकार से उम्मीद है कि कामर्शियल निवेश को भी इसमें जोड़ा जाए। एक करोड़ तक के निवेश से आने वाले रेंट को टैक्स फ्री किया जाए। - **मोहित सिंह राघव, एमडी, एमएमआर ग्रुप**

बाजार में मंदी, घर खरीदारों और उधार देने वाले बैंकों के बीच विश्वास की कमी के कारण वित्त मंत्री से आग्रह है कि इस क्षेत्र के लिए वन टाइम लोन पुनर्गठन की घोषणा करें। इससे निर्माण में तेजी आएगी। - **सागर सक्सेना, प्रोजेक्ट हेड, स्पेक्ट्रम मेट्रो**